जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 389 प्रभात हिण्डौन सिटी, बुधवार 3 दिसम्बर, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

अब झारखंड भी कांग्रेस के हाथ से निकलेगा, बिहार के चुनाव के कारण

झारखंड के मु.मंत्री हेमंत सोरेन तीन दिन से दिल्ली में हैं तथा गृह मंत्री अमित शाह से सम्पर्क में हैं। चर्चा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब इंडिया गठबंधन छोड़कर, भाजपा से हाथ मिलाएगा

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसंबर। कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य सरकार निकल सकती है।

कांग्रेस झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के साथ गठबंधन सरकार चला रही है, जिसका नेतृत्व हेमंत सोरेन कर रहे हैं।

विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि हेमंत सोरेन पिछले 3 दिनों से दिल्ली में हैं और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में हैं, जिसे साझेदार बदलने की उनकी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।

सोरेन की नाराज़गी और दुख की वजह बिहार में उनके प्रति कांग्रेस का व्यवहार है। बिहार में 30 से ज़्यादा सीटों पर आदिवासी वोटों का असर है और जब जेएमएम ने 6 सीटों की मांग की, तो कांग्रेस ने कह दिया कि आरजेडी वरिष्ठ साझेदार है और वही सीटें तय करेगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हेमंत सोरेन की नाराज़गी की शुरुआत हुई, जब उन्होंने कांग्रेस से बिहार की तीस ट्राइबल सीटों में से छः सीटों पर टिकट मांगा। पर, कांग्रेस ने यह कह कर बात टाल दी की आरजेडी बिहार में इंडिया गठबंधन की वरिष्ठ पार्टनर है। अतः आरजेडी ही निर्णय लेगी, सीटों के बंटवारे के बारे में।
- हेमंत सोरेन ने जवाबी तर्क दिया कि कांग्रेस उसकी 35 ट्राइबल सीटों में से 2 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे दे और फिर वे सभी 36 ट्राइबल सीटों पर जमकर चुनाव प्रचार कर सकेंगे।
- पर, ये दो सीटें भी सोरेन को नहीं मिलीं तो क्रोधित सोरेन ने राहुल गांधी के विशेष चहेते, बिहार के प्रभारी अलुवीरा को बहुत अपशब्द सुनाये और इंडिया गठबंधन छोड़ने का निर्णय लिया।
- 42 सदस्यी विधानसभा में कांग्रेस के 16 विधायक हैं तथा आरजेडी के चार, अतः हेमंत सोरेन का आकलन है कि अगर इंडिया गठबंधन के 20 विधायक चले भी जाते हैं तो भाजपा के 21 विधायक उनके समर्थन में आ जाएंगे और सरकार चलती रहेगी।

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

जयपुर, 2 दिसंबर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कुलदीप कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि चिकित्सीय साक्ष्य और पीड़िता के बयानों से साबित है कि अभियुक्त ने उसके साथ संबंध बनाए हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 15 फरवरी 2021 को विश्वकर्मा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि वह एक फैक्ट्री में काम करता है और परिवार सहित उसी परिसर में रहता है। बीती रात से उसकी नाबालिग बेटी घर से लापता है। उसे आसपास तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चला। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने फरवरी 2021 के मामले में फैसला सुनाया।

एसआईआर के खिलाफ संयुक्त प्रदर्शन से कतराए कुछ विपक्षी दल

तृणमूल कांग्रेस, जेएमएम और सपा, कांग्रेस के साथ खड़े नज़र आना नहीं चाहते

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसंबर। संयुक्त विपक्ष, जिसने वंदे मातरम् विवाद और एसआईआर पर संसद में चर्चा करवाने के लिए मोदी सरकार पर दबाव बनाने में सफलता पाई थी, में अब दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। 'इंडिया' गठबंधन के बनने के बाद पहली बार विपक्ष इस बात पर बंटा हुआ दिख रहा है कि एसआईआर के खिलाफ संयुक्त प्रदर्शन किया जाए या नहीं-और यह दरार अब तक दिखाई पड़ी उनकी संयुक्त राजनीतिक चुनौती को कमज़ोर कर सकती है।

वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, समाजवादी पार्टी (सपा) इस समय कांग्रेस के साथ बहुत नज़दीक दिखने को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान है। हाल ही में बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली हार-जिसमें कांग्रेस एक प्रमुख सहयोगी थी-ने सपा को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कांग्रेस से निकटता कहीं चुनावी जोखिम न बढ़ा दे।

सपा के अंदरूनी लोग मानते हैं कि पार्टी इंडिया गठबंधन के भीतर अपने तालमेल की रणनीति पर दोबारा विचार कर रही है, खासकर उन राज्यों में, जहाँ भाजपा के लिये मुख्य चुनौती है। मुख्य चुनौती सूत्रों ने यह भी कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस 403 सीटों वाली विधानसभा में 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है।

इस तनाव को और बढ़ाते हुए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कांग्रेस से नाराज़ बताए जा रहे हैं, क्योंकि हाल की रणनीतिक बैठकों में उनकी पार्टी जेएमएम को किनारे कर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सपा के आंतरिक सूत्रों ने बताया कि पार्टी कांग्रेस के साथ तालमेल पर दोबारा सोच रही है और इसलिए वह कांग्रेस के ज्यादा निकट नज़र आने से कतरा रही है।
- ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल पहले ही कांग्रेस नेतृत्व वाली सामूहिक रणनीति से दूरी बना चुकी है। अरविंद केजरीवाल पहले ही इंडिया गठबंधन से अलग हो चुके हैं।
- झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार के रवैये के कारण कांग्रेस से नाराज़ है।
- देखना यह है कि क्या विपक्ष का गतिरोध एसआईआर व वंदे मातरम मुद्दे पर विपक्ष के सामूहिक विरोध की हवा निकाल देगा?

एक अन्य कांग्रेस प्रभारी राजस्थान ट्राइबल इलाके का कुण्डा करने में लगे हैं

मेवाड़ की सात सीटों (उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बाँसवाड़ा, राजसमंद, सलूंबर व प्रतापगढ़) में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्तियाँ चौंकाने वाली हैं

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसंबर। राहुल गांधी लगातार ओबीसी समुदाय की बात करते हैं और कहते हैं कि उनकी जनसंख्या के अनुसार उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

लेकिन राहुल को उनके प्रिय "संगठन सृजन अभियान" में पूरी तरह गुमराह किया गया है, और ऐसा लगता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि यह सब कैसे, कब और कहाँ हुआ।

मेवाड़-उदयपुर ज़िले में एआईसीसी के प्रभारी रंधावा, सीपी जोशी से सलाह-मशविरा करके काम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- तीन जिलाध्यक्ष (उदयपुर ग्रामीण, डूंगरपुर व बाँसवाड़ा) ही ट्राइबल हैं।
- दो जिलाध्यक्ष (उदयपुर सिटी व चित्तौड़गढ़) राजपूत हैं।
- प्रतापगढ़ में भी दो परस्पर विरोधी राजपूत ग्रुप्स की प्रतिस्पर्धा में नियुक्ति पैंडिंग है।
- राहुल गांधी बार-बार कह रहे हैं, ओबीसी जनता को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, उनकी जनसंख्या के अनुरूप। अतः राहुल ये सामाजिक संतुलन बिठाने पर बहुत जोर दे रहे है तथा विशेषकर, मेवाड़ में सबसे अधिक जनसंख्या ट्राइबल्स की है तथा दूसरे नम्बर पर हैं ओबीसी।

प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम 'सेवा तीर्थ'

नई दिल्ली, 2 दिसंबर। केन्द्र सरकार ने एक अहम् फैसले में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) वाले नए परिसर का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया। सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्मित यह परिसर जल्द ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नया कार्यालय होगा। पहले इस जगह को एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव नाम दिया गया था।

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि सेवा तीर्थ को एक ऐसा कार्यस्थल बनाया जा रहा है, जहां सेवा भावना ही सर्वोपरि होगी और राष्ट्रीय स्तर की प्राथमिकताएं आकार लेंगी। सेवा, कर्तव्य और पारदर्शिता को शासन का आधार बनाने के प्रयासों के तहत, राज्यों में राज्यपालों के आवास के नाम राजभवन से बदलकर लोकभवन करने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सभी राज्यों के राजभवन अब लोक भवन कहलायेंगे।

सेना ने इमरान की बहनों को इमरान से मिलने दिया

इमरान को स्वस्थ व खुश देखकर, सस्पैंस तो खत्म हुआ, पर, सेना अभी असमंजस की स्थिति में है इमरान के बारे में

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसंबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो अगस्त 2023 से जेल में हैं, को आखिरकार एक बड़ी राहत मिली, जब जेल प्रशासन ने आखिरकार उनकी बहनों को उनसे मिलने की अनुमति दे दी। इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ (पी.टी.आई.) ने इमरान खान से मिलने की मांग को लेकर देशभर में लगातार जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए।

जेल अधिकारियों की अनुमति मिलने के बाद उनकी बहनों ने इमरान खान से मुलाकात की और बताया कि पूर्व क्रिकेटर और पूर्व प्रधानमंत्री पूरी तरह ठीक हैं।

इस बीच, पड़ोसी देश भारत में इमरान की सेहत को लेकर चिंता इस प्रकार बढ़ रही थी, मानो कोई बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो गया हो। राजनेता और मीडिया लगातार इमरान की सेहत और उनको होने वाले खतरों के बारे में बेचैनी से लिख रहे थे।

इस मुद्दे को लेकर भारत में सोशल मीडिया का माहौल गर्मा गया था। एक वर्ग इमरान की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, जबकि दूसरा कह रहा था कि इमरान एक कट्टरपंथी मुस्लिम हैं और कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों पर गंभीर हमलों में उनकी भूमिका रही थी।

सोशल मीडिया पर कई लोग यह भी कह रहे हैं कि इमरान के लिए दुःख जताने के बजाय, भारत को उन बड़े वैश्विक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जो भारत की सुरक्षा और हितों से जुड़े हैं।

फिर भी, इमरान खान भारत में खास रुचि का विषय बने रहते हैं। इसका एक बड़ा कारण उनका शानदार क्रिकेट करियर है, जिसने उन्हें भारत में भी लोकप्रिय बनाया।

लेकिन, अपने क्रिकेट के दिनों से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- इमरान पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, सेना की इच्छा व मदद से। पर, शीघ्र ही मतभेद उत्पन्न हो गए, दोनों के बीच और इमरान को अपना पद छोड़ना पड़ा।
- इमरान के सेना के साथ संबंध कभी नरम, कभी गरम चलते रहे।
- पर, अब सेना, शाहबाज़ शरीफ से भी ज्यादा खुश नहीं है। अतः मिश्रित भावनाओं के बीच इमरान राजनीति के सैन्ट्रल स्टेज पर आ गए हैं, 23 अगस्त से लगातार जेल में कैद होने के कारण।
- क्या सेना कुछ नरम हुई है, इमरान के प्रति। अतः, एक बार और प्र.मंत्री बन सकते हैं, इमरान, अगर मधुर संबंध चलते रहे, सेना व इमरान के बीच। नहीं तो कई नाटक देखने पड़ेंगे, पाकिस्तान के राजनीतिक मंच पर।

इंडिया गठबंधन की नई रणनीति बनाने के लिये बैठक आज

नयी दिल्ली, 02 दिसम्बर। लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने को लेकर मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में सरकार तथा विपक्षी दलों के बीच बनी सहमति के बाद, अब विपक्षी इंडिया गठबंधन ने संसद में अपनी रणनीति पर नये ढंग से विचार करने के लिए संसद भवन परिसर में बैठक बुलाई है।

इंडिया गठबंधन के सूत्रों के अनुसार, बैठक बुधवार सुबह 09.45 बजे राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के चेम्बर में होगी, जिसमें गठबंधन के सदन के नेता संसद में सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सरकार और विपक्ष में संसद चलाने पर हुई सहमति के बाद खड़गे के चेम्बर में मीटिंग होगी।

पावर ब्रेकफास्ट के बाद मिले कर्नाटक में परिवर्तन के संकेत

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, पार्टी जो भी फैसला लेगी, हम उसे स्वीकार करेंगे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसंबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को बेंगलुरु में अपने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (डीकेएस) से उनके बेंगलुरु-स्थित आवास पर 'पावर ब्रेकफास्ट' के लिए मुलाकात की। यह बैठक अन्य परिस्थितियों में देखी जाती तो सामान्य लग सकती थी।

इस विवाद का केन्द्र एक समझौता है, जो कथित तौर पर कांग्रेस की 2023 की चौंकाने वाली चुनावी जीत के बाद हुआ था, कि सिद्धारमैया और डीकेएस पांच साल का कार्यकाल साझा करेंगे, यानी दोनों में से प्रत्येक मुख्यमंत्री के तौर पर ढाई साल काम करेगा।

ये दोनों कांग्रेस नेता, जो 2023 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर आपस में झगड़ रहे थे, नाश्ते पर मिले, जिसमें इडली, देसी चिकन करी और कॉफी (मुख्यमंत्री के लिए कम दूध वाली) के साथ दोनों ने चर्चा की। लेकिन इसका परिणाम अनिश्चित बना हुआ है, खासकर इसलिये कि सिद्धारमैया ने यह बताया कि दोनों ने आगामी कर्नाटक विधानसभा सत्र के बारे में बात की।

लेकिन सम्भवतः इस प्रकार की अपनी पहली स्वीकारोक्ति के रुप में, कि मुख्यमंत्री के रूप में उनका समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, सिद्धारमैया ने यह भी संकेत दिया कि जब भी कांग्रेस के शीर्ष नेता उनसे कहेंगे, वे पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, "पार्टी, विशेष रूप से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय हम दोनों को स्वीकार होगा।"

सूत्रों ने कहा कि दोनों को दिल्ली बुलाए जाने की संभावना है, जहां वे 8 दिसंबर को उन नेताओं से मिल सकते हैं। योजना के अनुसार, सदन स्थगित हो जाने के बाद दोनों नेता बेलगावी (जहाँ कर्नाटक विधानसभा स्थित है) से दिल्ली रवाना हो जायेंगे। सूत्रों ने समझाया कि यह यात्रा, जिसमें राज्य के कांग्रेस सांसद भी उनके साथ होंगे, एजेंडा के अनुसार, किसानों के मुद्दों और राज्य के जल संसाधनों के प्रबंधन को लेकर होगी। लेकिन बैकचैनल वार्ता भी एजेंडे में होगी।

उससे पहले, सिद्धारमैया, डीकेएस और वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल मंगलुरु में एक कार्यक्रम में एक मंच पर नजर आ सकते हैं, जो दिल्ली बैठक के लिए एक पूर्वाभ्यास हो सकता है।

समझा जाता है कि राहुल गांधी और खड़गे से उनकी रुबरु मुलाकात इस सत्ता-हस्तान्तरण योजना को तय करने में महत्वपूर्ण होगी और तीन वर्षों से चले आ रहे गतिरोध को समाप्त कर, कांग्रेस -शासित इस राज्य में स्थिरता की रक्षा करेगी। हालांकि, जैसा कि अधिकांश पार्टी मामलों में होता है, इस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- यह कह कर एक तरह से सिद्धारमैया ने भी पद छोड़ने के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं।
- अब जल्दी ही, संभवतया 8 दिसंबर को दोनों नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें भावी दिशा तय होगी।
- सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी और खड़गे सत्ता परिवर्तन का प्लान तैयार करेंगे, पर, जैसी कि परम्परा है, अंतिम फैसला राहुल लेंगे और यह संभवतया डीके शिवकुमार के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि राहुल कार्यकाल के बीच में सत्ता परिवर्तन पर असहमति जता चुके हैं।
- सूत्रों का मत है कि डीके शिवकुमार व सिद्धारमैया दोनों ही बदलाव पर सहमत हैं, पर, तारीख पर सहमत नहीं हैं। जहाँ डीके शिवकुमार जल्द से जल्द बदलाव चाहते हैं, वहीं सिद्धारमैया इसे जितना संभव हो सके, टालना चाहते हैं, संभवतया कार्यकाल खत्म होने तक।

एयरपोर्ट चैक - इन सिस्टम में तकनीकी खराबी आई

नई दिल्ली, 2 दिसंबर। अगर आप आज हवाई यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं तो आपको अपने लिये अतिरिक्त समय लेकर निकलना चाहिए, क्योंकि देश के कई एयरपोर्ट्स पर चेक-इन सिस्टम में तकनीकी दिक्कत आने से उड़ान सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इस वजह से कई एयरलाइंस की उड़ानें देरी से चल रही हैं, जिनमें एअर इंडिया की फ्लाइट्स भी शामिल हैं।

इसे लेकर एअर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि यह समस्या थर्ड-पार्टी सिस्टम में आई खराबी के कारण हुई है,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- देश भर के कई बड़े हवाई अड्डों से चैक-इन में तकनीकी खराबी आने से उड़ाने प्रभावित हुईं।